

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर - 198/2017

1. देवकरण पुत्र धन्नाराम दत्तक पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी खतेहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
 2. रामसिंह पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खतेहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
 3. नाहरू पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी खतेहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
 4. सुरेन्द्र पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी खतेहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू।
- उपरिथत अधिवक्ता

1. मौ० फारूक खान अधिवक्ता प्रतिवादी नं 1 की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी जी.ए. राज्य सरकार की ओर से

-वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र जगुराम जाति जाट निवासी जाखड़ों का वास तहसील व जिला झुंझुनू
2. गुगन पुत्र जगुराम जाति जाट निवासी जाखड़ों का वास तहसील व जिला झुंझुनू
3. रघुवीर सिंह पुत्र जगुराम जाति जाट निवासी जाखड़ों का वास तहसील व जिला झुंझुनू
4. मु. धापा स्त्री जगुराम पुत्र जगुराम जाति जाट निवासी जाखड़ों का वास तहसील व जिला झुंझुनू
5. परमेश्वरी स्त्री स्व. सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी खतेहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू राज।
6. सुमेर पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी खतेहपुरा तहसील व जिला झुंझुनू राज।
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. तहसीलदार (भू० अभिलेख) झुंझुनू।

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:- 24.10.2018

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। वाद वादीगण के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.2016 को वाद वादीगण खारिज कर निर्णय पारित किया गया था। जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
राज. (राज.)

राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के वहा निगरानी/टीए/7134/2016 पेश की गई। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.11.2016 के द्वारा निगरानी विचारार्थ ग्रहण किये जाने के स्तर पर 2000/- रुपये की कोष्ट पर सशर्त स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की गई कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को पुन नम्बर पर लिये जाने के आदेश देते हुए वादीगण को शेष प्रतिवादीगण की तलवी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का एक अतिम अवसर दिया गया है। आदेशानुसार पुन दर्ज रजिस्ट्र किया गया। माननीय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वादीगण ने प्रतिवादीगण की रजिस्टर्ड तलवी पेश नहीं की गई। जबकि रजिस्टर्ड तलवी पेश करने का दायित्व स्वयं वादीगण का है। परन्तु न्यायालय मत पर प्रतिवादीगणों को सूचना नोटिस जारी किया गया। प्रति न0 1 की ओर से मौ0 फारुक वकील उपस्थित हुआ वादीगण न0 1 व 2 ने एक प्रार्थना-पत्र रथगन के बावजूद भी तारबन्दी करने बाबत का पेश किया गया जिसके बाबत तहसीलदार झुन्झुनू को मौके कमिश्नर नियुक्त कर प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों बाबत रिपोर्ट भंगवाई गई तहसीलदार झुन्झुनू ने मौके पर रास्ता चालू होना कोई तारबन्दी नहीं होना अपनी रिपोर्ट में अंकित किया। वादीगण 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं होने पर न्यायालय के आदेश दिनांक 23.05.2018 के द्वारा खारिज किया गया। वादीगण द्वारा यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण दावा दावा घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरुस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर वाद पत्र में अवैध निर्माण नपती के अभाव में किया गया को तुड़वाने व हाल ख0न0 27 रकबा 0.10 है0 घाही की जगह नौ0 मुमकीन रास्ता घोषित कर दुरुस्त करने का अनुतोष चाहा गया है। हमने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के आदेश दिनांक 28.11.2016 व मौका रिपोर्ट तहसीलदार तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए बहस वकील उभावपक्ष पर बगौर मनन किया गया। वादीगण द्वारा वांछित अनुतोष घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरुस्ती चाहा गया

है। जो सम्भव नहीं है। क्योंकि घोषणा का अर्थ है कि प्राप्त होने वाले अधिकारों को रक्षा करना व रिकार्ड दुरुस्ती का अर्थ है कि पूर्व के रिकार्ड आधार पर नये रिकार्ड बनाते हुए त्रुटि को दुरुस्ती किया जाना है। इस वाद में दोनों ही स्थितियाँ नहीं हैं। बल्कि घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरुस्ती की आड़ में वादीगण नया इन्द्राज चाही भूमि से गै0मु0 रास्ते के रूप में करवाना चाहते हैं। यह अनुतोष वादीगण को इस वाद के जरिये दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार वाद वादीगण सिद्ध नहीं होने से खारिज योग्य है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो। आज निर्णय दिनांक 24.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अलका बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

उपखण्ड अधिकारी

झुंझुनू (राज.)